

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 662 व 663/2011/नागौर

सहायक आयुक्त, नागौर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गोविन्द रेडियो सेन्टर, नागौर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अरिंजय जैन, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20.02.2014

निर्णय

यह दोनों अपीलें सहायक आयुक्त, नागौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) अजमेर, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के क्रमशः अपील संख्या 66/2009-10/वेट/नागौर व 55/2010-11/वेट/नागौर में पारित किये गये पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 10.12.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश क्रमशः दिनांक 24.03.2010 (निर्धारण वर्ष 2006-07) व दिनांक 22.03.2010 (निर्धारण वर्ष 2007-08) के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के विवादित तथ्य सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2006-07 व 2007-08 का वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2010 व दिनांक 22.03.2010 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि के दौरान उसके द्वारा बिक्रीत माल की उत्पादक कम्पनी मैसर्स टाटा इण्डिकाम टेली सर्विसेज लिमिटेड (TTSL) द्वारा प्रमोशन स्कीम के तहत रुपये 2,08,32,753/- व 1,92,32,786/- की सब्सिडी प्रदान की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी को उक्त राशि के प्राप्त होने की जानकारी विक्रय से पूर्व थी एवं वेट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार व्यवहारी को मिलने वाली सब्सिडी भी consideration for sale होने के कारण विक्रय मूल्य का भाग है, इसलिए उक्त

लगातार.....2

सब्सिडी राशि रूपय 2,08,32,753/- व 1,92,32,786/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 8,33,310/- व 7,69,312/- का आगत कर का मुजरा रिवर्स कर, कर आरोपण किया गया। इसी प्रकार प्रथम प्रकरण में त्रैमासिक विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति 70/- व सत्यापन के अभाव में 12,611/- समायोजन नहीं प्रदान कर, आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 10.12.2010 से अपील स्वीकार की जाकर करारोपण को अपास्त किया, जिसके विरुद्ध यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आरोपित कर को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। उनका कथन है कि व्यवहारी जानबूझकर विक्रय मूल्य कम वसूल कर सब्सिडी द्वारा विक्रय मूल्य का पुनर्भरण कर रहा है तथा उस पर कर अदा नहीं किया जा रहा है। सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग होते हुए भी अपीलीय अधिकारी ने कर को अपास्त कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार व्यवहारी को विक्रेता से अतिरिक्त स्रोत से मिलने वाली सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब्सिडी बिक्रीत माल का consideration नहीं है। अपने कथन के समर्थन में 124 एस.टी.सी. 586 (SC) नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कुड्डलोर, 126 एस.टी.सी. 547 (SC) टिस्को जनरल ऑफिस रिक्रिएशन क्लब बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य एवं 124 एस.टी.सी. 562 (SC) मद्रास रिफाईनरी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 26.08.2013 के न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ण खरीद पर विक्रेता को वैट भुगतान किया जाता है। विक्रेता द्वारा प्रत्यर्थी को कोई क्रेडिट नोट जारी नहीं किया जाता, न ही चुकाये गये वैट को लौटाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को तृतीय पक्ष मैसर्स टाटा इण्डिकाम टेली सर्विसेज लि० द्वारा

सब्सिडी दिये जाने को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी के रेकॉर्ड व उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने क्रेताओं को बिक्रीत माल के विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, बल्कि प्रत्यर्थी को उसके विक्रेता मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम के अतिरिक्त मैसर्स टाटा इण्डिकाम टेली सर्विसेज लिमिटेड (TTSL) द्वारा प्रदत्त सब्सिडी ही विवादित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसे Sale price का भाग मानते हुए तथा उसपर लाभांश जोड़कर वेट आरोपित किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम से Mobile Handsets & SIM/RVIM Cards (Starter kit etc.) क्रय करता है तथा मैसर्स TTSL से Telecom services for selling its services products such as starters kits/RCVS क्रय करता है। प्रत्यर्थी मैसर्स ड्राईव इण्डिया कॉम से जो हैंडसेट्स क्रय करता है, उसे क्रय मूल्य से कम पर विक्रय करता है तथा अन्तर मूल्य को मैसर्स TTSL से सब्सिडी के रूप में प्राप्त करता है। कर निर्धारण अधिकारी अनुसार यह सब्सिडी विक्रय मूल्य का भाग है। विक्रय मूल्य की परिभाषा वेट अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विहित की गई है, जो कि इस प्रकार है :-

2(36) “sale price” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**Explanation I.** – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

**Explanation II.** – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;



**Explanation III.** - Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

उक्त परिभाषा अनुसार विक्रेता को जो राशि माल के मूल्य के रूप में क्रेता से प्राप्त होती है, या होने योग्य है, वही विक्रय मूल्य का भाग है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2001) 124 एस.टी.सी. 586 में जहां फर्टीलाइजर पर सब्सिडी का प्रकरण विचाराधीन था, सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि (Para-15) -

15. It appears to us that the aforesaid observations are clearly applicable in the present case. Here also, there is no statutory basis for the grant of subsidy; and the amount was received by the appellant pursuant to the administrative decision taken by the Central Government. Furthermore, the subsidy is not traceable to any agreement, direct or indirect, between the manufacturer and the purchaser of fertilizer. What was payable in law as a sale price for fertilizer was the amount or the rate fixed under the Fertilizer (Control) Order and no more. This position is also made clear by the observations of this Court in M/S. George Oakes (P.) Ltd. v. State of Madras, [1962] 2 SCR 570, wherein a Constitution Bench observed that the expression turnover means the aggregate amount for which goods are bought or sold, whether for cash or for deferred payment or other valuable consideration, and when a sale attracts purchase tax and the tax is passed on to the consumer, what the buyer has to pay for the goods includes the tax as well and the aggregate amount so paid would fall within the definition of turnover. At page 580, it was observed that "so far as the purchaser is concerned, he pays for the goods what the seller demands, viz., price even though it may include tax. That is the whole consideration for the sale and there is no reason why the whole amount paid to the seller by the purchaser should not be treated as the consideration for the sale and included in the turnover." It is clear from the aforesaid observations that it is that amount which flows from the purchaser to the seller which alone would form part of the turnover of the seller. Any sum received de hors the contract of sale from another entity, whether it be



**Government or any one else, cannot be regarded as being an amount which would form part of the sale price on which tax is payable.**

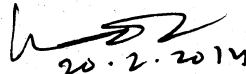
इसी प्रकार माननीय शीर्ष न्यायालय ने 124 एस.टी.सी. 562 में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि -

**".....the amount received by the appellant from the compensation pool. It is the case of the appellant that in the show cause notices, it is stated that the amount so received is to form part of the sale price and, therefore, would be includible in its taxable turnover. It is, however, contended that even if it be assumed that the amount received from the compensation pool would form part of the sale price, but, as the amount is received in connection with the sales made by the appellant to another oil company, namely, IOCL, then, by virtue of Explanation 1 referred to hereinabove, the transaction is not to be regarded as the first sale within the State. The amount received by the appellant as a sale consideration from out of the pool relateable to the said sale would, therefore, not be regarded as part of the taxable turnover at all....."**

प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रत्यर्थी को विक्रेता के अतिरिक्त मैसर्स TTSL द्वारा प्रदत्त सब्सिडी को विक्रय मूल्य का भाग मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण अविधिक रूप से किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर, आगत कर का मुजरा प्रदान करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इसी क्रम में अधिक जमा राशि का समायोजन के बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से सत्यापन बाद समायोजन हेतु उचित रूप से अपील स्वीकार की गयी है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति के बिन्दु पर विशिष्ट नोटिस जारी किये जाने के अभाव में आरोपित शास्ति 70/- को उचित रूप से अपास्त किया गया है। अतः पारित अपीलीय आदेश में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1817/2011/जोधपुर निर्णय दिनांक 26.08.2013 के आलोक में, व उपर्युक्त विवेचनानुसार किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
20.2.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य